

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

पत्र संख्या : 1/ अ0प्र0-1001/2008-सा0 प्र0-14660/

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

कन्हैया लाल साह,  
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

श्री संजय दूबे, भा0प्र0से0 (बी एच:2008),  
निगम आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर ।  
श्री संजय सिन्हा, भा0प्र0से0 (बी एच:2008),  
निदेशक, युवा कल्याण एवं खेल निदेशालय,  
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना ।  
श्री गोरख नाथ, भा0प्र0से0 (बी एच:2006),  
संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।  
श्री विजय कुमार, भा0प्र0से0 (बी एच:2007),  
संयुक्त सचिव, राज्यपाल सचिवालय बिहार, पटना ।

पटना-15, दिनांक: 06 नवम्बर, 2018


विषय :- लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में दिनांक 19.11.2018 से 14.12.2018 तक की अवधि में प्रस्तावित अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण-III के संबंध में ।

प्रसंग:- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-14275 दिनांक 31.10.2018.  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक-14275 दिनांक 31.10.2018 के माध्यम से अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण-III में भाग लेने की संसूचित अनुमति के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि अकादमी द्वारा प्रासंगिक प्रशिक्षण हेतु भवदीय मनोनयन स्वीकार नहीं किये गये हैं ।

2. अतः विषयांकित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है ।


विश्वासभाजन,

  
6.11.18  
सरकार के अवर सचिव ।

स्पीड पोस्ट/फैक्स/ई-मेल

ज्ञापनांक :1/अ0प्र0-1001/2018-सा0 प्र0- 14660 /पटना-15, दिनांक: 06 नवम्बर, 2018


प्रतिलिपि:- श्री के0 श्रीनिवास, भा.प्र.से., संयुक्त सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, प्रशिक्षण प्रभाग, ब्लॉक-4, पुराना जेएनयू कैम्पस, नया महरौली रोड, नई दिल्ली-110067/श्री राजेश आर्या, पाठ्यक्रम समन्वयक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी-248179 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
6.11.18  
सरकार के अवर सचिव ।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक :1/अ0प्र0-1001/2018-सा0 प्र0- 14660/पटना-15, दिनांक: 06 नवम्बर, 2018

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग/राज्यपाल के प्रधान सचिव, राजभवन, पटना/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
6.11.18

सरकार के अवर सचिव ।